हुआ तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेगी ।

माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी, जिनके दिल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सम्मान है, जिसका प्रमाण लोक सभा के इसी सत्र में स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर और उसे सम्माननीय बना कर एक प्रशंसनीय कार्य किया है, से निवेदन है कि इस असाधारण महत्व के कार्य में उन की समाधि की रक्षा के लिये व्यवस्था करने की कृपा करें । इस समाधि की रक्षा किया जाना इसलिए की आवश्यक है क्योंकि वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीय महत्व के कार्य को मैं सदन, सरकार और माननीय प्रधान मंत्री जी की जानकारी के लिए रख रहा हूं ।"

MR. DEPUTY-SPEAKER: Certain things which nave been read by you have not been approved by the Speaker. Only those things which have been approved by the Speaker will go on record. This is for your information.

14.52 hrs.

DOCK WORKERS (REGULATION OF EMPLOYMENT) AMENDMENT BILL—*Contd.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Dock Workers (Regulation of Employment) Amendment Bill.

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को मैंने अपनी बात शुरू की थी और अपनी बात पूरी नहीं कर पाया था ।

मैं एक बात तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो डाक वर्कस रेगूलेशन आफ एम्पलायमेंट एक्ट, 1948 है, यह बहुत पुराना पड़ गया है । इसलिए इसके जितने भी सेक्शन्स हैं, उन के जरिये से अगर इस सारे वर्क को रेगूलेट करें, तो निश्चित रूप से बहुत सारी कठिनाइयां इस सम्बन्ध में उपस्थित हो सकती हैं । इसलिए मैं बहुत सारे सेक्शन्स के सम्बन्ध में अपने विचार आप के सामने रखना चाहता हूं । इन सारे सेक्शन्स में कुछ तरमीम होनी चाहिए जिस से डाक में जो कामगार काम करते हैं, उन को सारी सुविधाएं मिल सकें । मैंने उस दिन आप से निवेदन किया था कि डाक्स के अन्दर जो वर्कर्स काम करते हैं, उन को रेगूलर करने के लिए पर्मानेन्ट और टेम्पोरेरी की व्यवस्था की बात इस में कही गई है मगर डाक्स में और भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, जिन के बारे में इस में कोई व्यवस्था नहीं की गई है जैसे आप के केजुअल वर्कर्स हैं, जो वहां काम करते हैं या और भी तरह के वर्कर्स हैं जो रेगुलर या पर्मानेन्ट एम्पलाइज के स्थान पर काम करते हैं । वे उन के स्थान पर काम करते हैं और वे आल्टरनेट रूप से काम करते हैं, जिन को कुछ स्थानों पर बदली के वर्कर्स के नाम से पुकारा जाता है । इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो एप्रेन्टिस के तौर पर डाक्स में काम करते हैं । ऐसे लोगों के लिए किसी प्रकार का प्रविधान इस नये एमेंडमेंट बिल में नहीं किया गया है या इस एक्ट में नहीं है । केवल इस प्रकार की बात इस में रखी गई है कि कोई एक्ट या बिल जब बनायेंगे, तो पार्लियामेंट के सामने रखेंगे । इस तरह से डाक वर्कर्स की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा । इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से इस बिल के

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

अन्दर होना आवश्यक है, जिससे जो वर्कर्स वहां पर काम करते हैं, उन को ठीक प्रकार से वर्क मिल सके और जितने वेजेज उन को मिलने चाहिए उतने वेजेज उन को मिल सकें।

इस में एक प्रावधान यह दिया गया है कि कोई भी वर्कर है, जिस को काम नहीं मिलेगा, तो उस को मिनीमम वेजेज दिये जायेंगे। मिनिमम वेजेज क्या होंगे। आज जो रेगुलर वर्क करते हैं, उन को 10, 15 या 20 रुपये रोज मिलता है। अगर वर्क नहीं मिलता है, तो काम के अभाव के अन्दर निश्चित रूप से ऐसी इन्डस्ट्रीज है, जहां पर उन को उतना पैसा बराबर मिलता है। अगर कोई अनफोरसीन चीज हो जाए, ऐसी बात हो जाए कि बिजली खत्म हो जाए और ऐसे साधन न हो जिन की वजह से कारखाना न चल सके, तो उस प्रकार की व्यवस्था में तो उन को वेजेज नहीं मिलेगा लेकिन यहां पर काम के अभाव में मिनीमम वेजेज देने की बात कही गई है, वह निश्चित रूप से ठीक नहीं है। उनको भी उसी प्रकार से पैसा मिलना चाहिए जिस प्रकार से उन लोगों को मिलना है जो कि वहां रेगुलर तरीके से काम करते हैं।

एक बात मैं एडवायजरी कमेटी के बारे में कहना चाहता हूं। इसके बारे में यह व्यवस्था की गयी है कि इसमें वर्कर्स से भी सदस्य लिये जायेंगे, जो कम्पनीज हैं, उनके प्रतिनिधि भी इसमें रखे जायेंगे और उनके साथ साथ गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। जहां तक वर्कर्स का ताल्लुक है उनका इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अगर आप वर्कर्स को सारी सुविधाएं देना चाहते हैं और उन्हें पूरी तरह से पार्टिसिपेशन देना चाहते हैं तो आपको यह देखना है कि वर्कर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज इसमें माइनारिटी में न रहें। आप इसमें बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त कर देंगे, एम्प्लाइज के रिप्रेजेन्टेटिव्ज उसमें आयेंगे। इस तरह से डाक वर्कर्स के रिप्रेजेन्टेटिव्ज जो होंगे वे माइनोरिटी में रह जायगे। इस तरीके से वर्कर्स के हितों का ठीक प्रकार से ख्याल नहीं रखा जा सकेगा। इसलिए मै आप से निवेदन करना चाहता हूं कि डाक वर्कर्स के हितों का आपको पूरी तरह से ख्याल रखना चाहिए और उनके इसमें आधे रिप्रेजेन्टेटिव्ज होने चाहिएं। चेयरमैन भी गवर्नमेंट नामिनेट करेगी। चेयरमैन भी वर्कर्स की तरफ से होना चाहिए। ऐसा चेयरमैन होना चाहिए जो कि वर्कर्स को रिप्रेजेन्ट करे ताकि वह वर्कर्स के हितों का अच्छी तरह से ख्याल रख सके।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जो वर्कर्स वहां काम करने वाले हैं, काम करते वक्त, मान लीजिए, किसी प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी और प्रकार की केजुअल्टी हो जाती है, या उनका किसी और प्रकार का नुक्सान हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके कम्पेनसेशन के बारे में इस बिल में कोई प्रावधान नहीं है, न कोई प्रावधान पुराने एक्ट में है। इस प्रकार का प्रावधान इसमें होना चाहिए कि ऐसी हालत में पूरे तरीके से उन्हें कम्पेनसेशन मिल सके। फिलहाल न पुराने एक्ट में यह प्रावधान है और न इस अमेंडमेंट बिल में है।

लेबर कोर्ट के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोर्ट एम्प्लायर और एम्प्लायी के बीच में डिसीजन नहीं कर सकती है। क्योंकि उसमें एम्प्लायर के प्रतिनिधि भी रहते हैं और लेबर के

भी प्रतिनिधि रहते हैं । इनके लिए एक इंडीपेंडेंट कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए । उसी कोर्ट के जरिये या ट्रिब्यु-नल के जरिये से जब कोई एम्प्लायर और एम्प्लायी के बीच में विवाद हो तो, उसके जरिये से ही फैसला होना चाहिए । इससे जल्दी से जल्दी फैसला हो सकेगा और जल्दी से जल्दी लेबर को इमदाद मिल सकेगी । इसी तरह से लेबर की सुरक्षा हो सकती है । इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की जानी चाहिए ।

वेल्फेयर फण्ड के बारे में भी आपने जिक्र नहीं किया है कि आप फण्ड किस प्रकार से क्रियेट करेंगे ? अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले में, माइका में जो फण्ड स्थापित किये जाते है वे रायल्टी के जरिये से किये जाते हैं । इस बारे में न तो एक्ट में कोई प्रावधान है और न इस अमेंडमेंट बिल में किसी प्रकार का प्रावधान है कि फण्ड स्थापित होगा तो वह किस प्रकार से होगा और कितना होगा ? आप किस प्रकार की वेल्फेयर एक्टीविटीज को चाल करेंगे और क्या इन्हें भी वे सारी सुविधायें प्रदान करेंगे जो कि अन्य क्षेत्रों के वर्कर्स को दी जाती हैं ? इस प्रकार का कोई जिक्र इसमें नहीं किया गया है ।

15 hrs.

कम्पनियों के द्वारा जो गलत काम किए जाते है और किसी कानून की खिलाफवर्जी की जाती है, मजदूरों के प्रति दुर्भावना बरती जाती हैं, उनको विक्टिमाइज किया जाता है, उस तरह के कार्यों के लिए जो आपने प्रावधान रखा है निश्चित रुप से वह बहुत कमजोर प्रावधान है । बड़े लोग जो गलती करते हैं, उस गलती को छिपाने के लिए वे मैनेजर या अन्य अधिकारी को जिम्मेदार ठहरा देते हैं और कह देते हैं कि उनकी भूल की वजह से ऐसा गलत काम हुआ है और सौ दो सौ रुपया उसके ऊपर फाइन कर दिया जाता है । इस प्रकार का प्रावधान करके हमने मालिकों को बरी कर दिया है । मैं समझता हूं कि इस तरह के जो गलत काम होते हैं उसके लिए मालिक को सजा होना चाहिये और वह भी जुर्माने के रूप में नहीं बल्कि सजा के रुप में होनी चाहिये ।

दफा 7 ए में के अन्दर जो आपने प्राविसो रखा है उससे बड़े बड़े एम्प्लायर्ज के बच निकलने का रास्ता आपने खोल दिया है । इस प्रकार का प्राविसो निश्चित रुप से इसमें नहीं होना चाहिये। इसको डिलीट किया जाना चाहिये । इससे बड़े एम्प्लायर अपनी गलती से बच निकलेंगे और छोटे कर्मचारियों को फंसा करके छोटी मोटी सजा उनको दिलवा दगे । यह व्यवस्था समाप्त की जानी चाहिये ।

वैलफेयर एक्टिविटीज के सम्बन्ध में आपने तीन चार बात रखी हैं । उस में हाउसिंग हैं, मैडिकल है, एसंशियल आर्टिकल्ज देना, स्कालरशिप आदि का जिक्र किया है । इसके साथ साथ अन्य और साधनों की भी आवश्यकता होती है । उन साधनों की आप किस प्रकार से व्यवस्था करेंगे ? निश्चित रुप से कोई न कोई व्यवस्था इन मजदूरों के बच्चों, इनके परिवार वालों तथा दूसरे वहां रहने वालों की भलाई के लिए होनी चाहिये । ऐसी वैलफेयर एक्टिविटीज को चलाया जाना चाहिये जिससे उनको एक्सट्रा इनकम हो सके । उनको सिखाया पढ़ाया जाना चाहिये । जो कार्य दूसरे वैलफेयर फंडज के जरिये किए जा रहे हैं और उनके बारे में जो प्रावधान उन फंडज में हैं, वे यहां भी होने चाहिये ।

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

अब मैं बोर्ड के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । दफा 6 सी बी में आपने प्रावधान किया है कि बार्ड अगर कोई भी गलती करता है या वह कोई इरेग्युलैरिटी कर देता है तो गवर्नमेंट उसको रेग्युलराइज कर देगी । यह नहीं होना चाहिये । कोई भी आदमी जो बोर्ड में रहता है वह कोई गलत काम करता है, इरेग्युलैरिटी करता है तो निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर फिक्स होनी चाहिये और उसको इसकी सजा मिलनी चाहिये । उस ने इस प्रकार से रूल्ज का कंट्रेवेशन करके जो गलती की है उसकी उसको सजा मिलनी चाहिये । बड़े आदमी जो बोर्डस में बैठते हैं वे दिन रात गलतियां करते हैं फंड्ज का दुरुपयोग वे अगर करते हैं तो इस प्रकार से उनको बरी नहीं कर दिया जाना चाहिये । ऐसा आपने कर दिया तो जो अव्यवस्थायें होती हैं उनको आप रोक नहीं पायेंगे । इसकी उन के ऊपर रिस-पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिये । जो डिफैक्टिव काम करे, जो इरेग्युलैरिटी करे, फंड्ज का दुरूपयोग करे निश्चित रूप से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिये और उनको सजा मिलनी चाहिये ।

15.04 hrs.

[SHRI SHIVRAJ V. PATIL *in the Chair*]

डिस्क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में आपने 8 (2) (एफ) प्रावधान इस में दिया हुआ है। कौन से कारण हैं जिन की वजह से कोई डिस्क्वालिफाई हो जाएगा इसका आपने जिक्र नहीं किया है। एक्ट में भी इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि आपने खुली छूट दे दी है जिससे किसी को भी डिस-क्वालिफाई किया जा सकता है और उसको मम्बर रहने लायक नहीं रखा जा सकता है। इसलिऐ डिसक्वालीफिकेशन के सम्बन्ध में उसका विवरण होना चाहिये कि इस प्रकार की कार्यवाही करने वाले के साथ एक्शन हो सकता है । जब तक यह व्यवस्थाएं नहीं होंगी निश्चित तौर के से इनके बिना किसी भी आदमी को मेम्बर-शिप से हटाया जा सकता है जो कि ठीक प्रकार से काम करता है । यह सारी व्यवस्थाएं डाक वर्कर्स के लिये हमको करनी हैं । इसके साथ-साथ डाक्स में जिस प्रकार की अन्य अव्यवस्थाएं आज है, उनको भी आपको देखना है उनके हितों के सम्बन्ध में जब हम ध्यान रखते है तो उनके कर्तव्यों के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है ।

आज कलकत्ता में क्या हो रहा है ? वहां डाक्स में व्यापारी लोग अपना सामान ले जाते हुए हिचकिचाते हैं। वहां जो भी सामान ले जाते हैं वह गायब हो जाता है। वहां रेल के डिब्बों की एक-एक कील तक गायब हो जाती है । इस प्रकार की हालत कलकत्ता के डाक यार्ड की है। ऐसी स्थिति अन्य डाक-यार्डस में भी अगर पैदा होती है तो उससे आपके विभाग को बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसकी प्रतिष्ठा भी खराब होती है । कलकत्ता में आज से 5,10 साल पहले जितना सामान डाक्स के जरिये भेजा जाता था आज उसकी परसेन्टेज में कितनी गिरावट आई है यह देखने की बात है । कलकत्ता के सम्बन्ध में तो मैंने अखबार में पढ़ा था इसलिये मैंने आपसे निवेदन किया है, दूसरी जगहों पर भी शायद ऐसी ही हालत होगी । वहां जो यूनियन है उससे डाक्स के लोग प्रभावित होते हैं । उस यूनियन के लोग वहां किस प्रकार का काम कर रहे हैं; किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, अगर इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ध्यान नहीं देंगे तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्ट जिसके जरिये सबसे ज्यादा आमदनी होती है सबसे ज्यादा लोडिंग और अन-लोडिंग होता है वह

समाप्त हो जायेगा । वहां इस प्रकार की अव्यवस्था हो जाती है तो निश्चित तौर से हमारे देश के लिये यह एक ऐसी प्रतिष्ठा का सवाल पैदा हो जाता है जिससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। इसलिये इन व्यवस्थाओं को सही तरीके से ठीक करने की आवश्यकता है।

डाक्स में काम करने वाले वर्कर्स का विक्टमाइजेशन नहीं किया जाना चाहिये; लेकिन जो ठीक काम नहीं कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके साथ ही ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिये कि जो वर्कर ईमानदारी से काम करता है डाक को ऊंचा उठाने की कोशिश करता है उसकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है उसको अवश्यक लाभ मिलना चाहिये । इन बातों को निश्चित तौर पर आवश्यकता है।

जो बातें मेरे सामने आई हैं उनके सम्बन्ध में मैंने आपसे निवेदन किया है और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो अमेंडमेंट वह लाये हैं इनसे काम नहीं चलेगा उनको पूरा बिल इसके बारे में लाना पड़ेगा जिसमें वर्कर्स की सुविधाओं के सम्बन्ध में सारी बातें आ सकें। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि वह इस प्रकार का पूरा बिल संसद् के सामने लायें ताकि कर्मचारियों के हितों और वहां की व्यवस्था सुचारु रूप से चल सके और आप के फंड्ज का उपयोग ठीक प्रकार से हो सके । जब तक वहां ऐसे लोग बैठे रहेंगे, जिन्होंने कि फंडस का दुरुपयोग किया है तो निश्चित रूप से फन्ड्स का उपयोग नहीं होगा ।

अभी भी वहां पर 50 परसेंन्ट से ऊपर फंड का उपयोग अधिकारियों पर खर्च हो रहा है और डाक पर काम करने वाले कर्मचारियों की सुविधाओं के लिये वह पैसा बिल्कुल खर्च नहीं हो पाता है, इसकी तरफ मैं विशेष तवज्जह आपका दिलाना चाहता हूं। मेरा निवेदन है कि इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए आप एक नया बिल लाइये जिसके जरिये आप इन डाक-याड्स के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दे सकें ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली): सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि जब सबआर्डिनेट लेजिस्लेशन सम्बन्धी कमेटी ने उनका ध्यान आकर्षित किया, तो उन्होंने इस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया। यह काम बहुत दिनों के बाद हुआ है, लेकिन हो गया, इस के लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मई 1980 के **रीडर्ज डाइजेस्ट** में प्रकाशित एक आर्टिकल के एक पैराग्राफ की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं :—

"One prize-winning slogan coined by a Mazagaon Dock employee reads: "We can make a hull, but not your skull." Says A. S. Abraham, who headed Mazagaon's safety department for years, "Only when people realise that human beings are irreplaceable will they really become safety conscious."

मैं इस सारे आर्टिकल को तो नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन इसमें बताया गया है कि 1972 में 1700 आदमियों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ा। 1978 में यह संख्या कुछ कम हुई। इस आर्टिकल में कहा गया है कि हिन्दुस्तान में आदमी बहुत सस्ता है और मजदूरी करने वाले व्यक्ति की सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उसमें कहा गया है :—

"Every one-and-three-quarter minutes, somebody gets hurt or maimed in an Indian factory. Who is to blame, and how can the growing number of victims be reduced?"

[श्री मूल चन्द डागा]

इस सम्बन्ध में 19 जून, 1980 को एक क्वेश्चन किया गया था, जो इस प्रकार है:—

"(a) Whether Government have set up a 12Member Wage Panel to go into the demands of port and dock workers for wage revision;

(b) If so, the terms of reference of the panel and constitution of the panel;

(c) Whether the representatives of the workers have also been associated with the panel; and

(d) When the report of the panel is like to be submitted?"

इस क्वेश्चन का जवाब बहुत लम्बा चौड़ा दिया गया था। मुझे यह बात अच्छी लगी कि जो बाईपार्टाइट वेज नेगोशिएशन्ज होंगी उनमें एम्प्लाइज को भी शामिल किया जायेगा। जवाब इस प्रकार था :—

"(a) Government have set up a Bipartite Wage Negotiating Machinery with 10 representatives each employers and workers on 14-5-1980.

(b) The Bipartite Wage Negotiating Machinery will negotiate the revision of the existing 'wage structure' including all matters considered by the Wage Revision Committee for Port and Dock Workers, and allied matters agreed to be discussed by the Negotiating Machinery, for the Class III and Class IV employees of (a) major Port Trusts; (b) Dock Labour Boards; (c) Administrative Bodies of the Dock Labour Boards...."

"No time limit has been fixed for completion of the negotiations and arriving at a Settlement."

लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया है कि किस तारीख तक समझौता हो जायेगा। यह कदम 14 मई, 1980 को उठाया गया था। आज कितने वर्ष बीत बीत चुके हैं, उसके बाद भी कुछ परिणाम नहीं निकल रहे हैं। मैं यही आप से कहना चाहता था। ऐक्ट के अंदर जो आप ने संशोधन किया है यह बहुत अच्छा किया है। इस से एक बहुत बड़ा वेलफेयर फंड खुलेगा और उस में उन के वेलफेयर ऐक्टिविटीज के लिए काफी धन इकट्ठा होगा। इस में आप ने बड़ी होशियारी से यह काम किया कि कोई भी आदमी कोर्ट में नहीं जा सकता; यह बहुत अच्छा किया नहीं तो शायद एम्पलायर्स कोर्ट में चले जाते। आप ने यह भी एक सेफ्टी का स्टेप लिया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह जो बाइ-पार्टाइट ऐग्रीमेंट है, इस में कब तक यह निर्णय ले लेगा ? डाक वर्कर्स की सेफ्टी का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। उन की सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। इसीलिए आप ने यह फंड कायम किया है। मैं आशा करता हूं कि आप इस तरफ ध्यान देंगे।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): This Bill, of course, on the face of it, is of a technical nature, but I would like to take this opportunity to say one or two things.

My friend Shri Daga, I think, is a bit misinformed. He does not perhaps know that this Bill is not going to lead to the creation of any new fund. The funds are there already. There was no specific provision in the Act and the scheme enabling them to create these funds, and that is now being included as per the recommendation of the Committee on Subordinate Legislation. Funds for welfare purposes of the dock workers are there. They are created out of levies which are imposed on the employers. That is, on the stevedores and the shipowners. The point is that there is not any new fund. But what I wish to point out now is that although this Act has been in force since 1948, and 32 years have passed, the urgent welfare measures for which these funds should have been utilised, of which I

think the two most important are housing and hospitalisation, have not been taken so far. Let the hon. Minister tell us what has been done in all these years.

There is no housing scheme in this country for the dock workers. I hope everybody knows that there is a distinction between the workers of the Dock Labour Board and Port Trust workers. They are working side by side, but they are two different sets of workers. The port workers are employees of the Port Commissioners or Port Trusts, and they do not actually get on to the vessels, but work on the shore side. After the cargo is taken out from the ships, they handle them. This Bill refers to the workers of the Dock Labour Board who work on board the vessel, who get on to the vessel and take the cargo out of the hatches of the ship.

For example, in Calcutta, to which reference has been made by another friend here, there are 14,000 dock workers registered under the Calcutta Dock Labour Board, but there is not one single house, hut or quarter built for these men up to this day since 1948, and the main reason for this, apart from maladministration and the corruption of the administration of the Dock Labour Board, is the fact that these dock workers are not counted in the eyes of the law as industrial workers in our country. They are not classified as industrial workers. The Minister knows this very well. Labour laws as they exist in our country never classified them as industrial workers, those who are employed or who come within the definition of the Factories Act. Dock workers are excluded. If you are classified as an industrial worker, then the industrial housing schemes which are formulated by the Government and for which Government gives financial assistance, become available, but the dock workers cannot take any advantage of these industrial housing schemes because they are not counted as industrial workers at all. So, it was the job of the Dock Labour Board and the administrative bodies of these Dock Labour Boards to utilise this welfare fund in order to construct houses for these workers, but nothing has been done till this day.

I wish Members go to Calcutta and see the conditions in which these dock workers live, the horrible, congested, stinking, insanitary hovels in the bustees where they have to live. In one room 15, 20 or 25 people live, because no accommodation is available and one set of workers go to work in the day time, in their absence, the people who are to work at night, are sleeping in that room and when those people go back from duty, then this set of workers goes to work at night on night-shift and then only there is room for these people to lie down and sleep. This is the condition in which they are. No housing facility has been provided. The Government should answer this, why for all these years so much neglect has been there of a section of workers who are supposed to be doing a very vital job for this country and without whom no ships can be loaded or unloaded in any of the major ports in this country.

In Bombay there is some meagre housing for the dock workers, but that is also absolutely inadequate. In Calcutta, there is no housing at all, not a single house. So, what I wish to say is that it is not enough to come forward with a technical Bill of this nature saying that legally and formally there should be a provision for creation of funds. The funds are there. But the point is that, why should these dock workers not be brought within the purview of the industrial workers, why should they not be on par with other workers who are counted as industrial workers so that they can be eligible for the benefits of the Government's Industrial Housing Schemes, for which the Government provides money, provides financial assistance, because it is quite obvious that the Dock Labour Board Administrative bodies and managements are not going to do anything. They could not care less. There is so much unemployment unfortunately in the ports and docks, so many people are there looking for jobs, that

[Shri Indrajit Gupta]

they do not think it necessary at all to provide any housing or any suitable facility for them at all. As you know, the Dock Labour Board workers constitute a pool. They are not attached to any particular employer, they are not like the employees of Port Trust. There is a list of Registered workers, they constitute a common pool, gangs of workers are drawn from that pool as and when required. When the vessels come to the port, when there are enough vessels, then most of the peoples get work. When the flow of vessels goes down in a particular seasen or month, when there is no work, then, of course, it is true that they get the minimum guaranteed pay under the Dock Workers' Schemes. That is why it has been provided. But they are not stable employees of any particular employer, nobody bothers about them, nobody bothers about their welfare facilities at all. They must be treated on par with industrial workers. This Act was passed in 1948 and we are now in 1980. I think it is high time that the Government should tell us why this kind of discrimination, statutory discrimination against these dock workers is continued to be practised.

Then the other point I wish to make is, how far this has gone. There is a Dock Labour Board hospital. Of course, Mr. Minister, you have been to Calcutta several times and seen. There is a Dock Labour Board hospital there, but when compared with the hospital provided for the Port Trust employees, I should say that it compares very unfavourably. Anyway, in that Dock Labour Board hospital, for the nurses, for example, for the female nurses, who are employed there, there are no quarters. They have to live miles and miles away and everybody knows what the conditions are in and around Calcutta. They have to go everyday 20, 30 or 40 miles to reach their place of duty. The transport system is on the verge of breaking down. As every body knows, the congestion is so much that the possibility of your reaching the place of work on time has become a nightmare for millions of office-goers and factory-goers in Calcutta. These nurses who are supposed to be on duty promptly and punctually to look after the patient, even they are not provided with quarters in the hospital compound. There is not a single quarter. They are ladies, women and they are expected to go all round the clock, day time and night time, there are night duties also—how are they to come and go? They have been raising this demand and ventilating this grievance for a long time, but nothing has been done about it. The hon. Minister knows that things have come to such a pass that the administrative body of Calcutta Dock Labour Board has been suspended, it has been suspended at present on grounds of corruption and malpractices. It has been suspended. There is no administrative body at present.

AN HON. MEMBER: Which body?

SHRI INDRAJIT GUPTA: Each Dock Labour Board under the scheme has got an administrative body. In that administrative body labour is not represented. The administrative body consists only of the employers—the Chairman of the Dock Labour Board and the representatives of the employers. Strangely enough, there is no representative of workers on that administrative body. The administrative body in the Calcutta Dock Labour Board stands suspended today—he knows it—on grave charges of corruption and mal-practices. All the unions, whether it is a Congress union or a CPI union or a CPM union or any union, have told the Minister, "Please don't try to restore this corrupt administrative body again."

We are told that certain employers are trying to put pressure on the Ministry also to see that they are cleared of the earlier charges and the body is restored so that they can go on merrily defalcating the funds and all that which are supposed to be spent for welfare measures. I hope, the Minister will not yield to any pressure and that the corrupt administrative body will not be restored or reinstated. If

an attempt is made to restore that body, I am afraid, there will be considerable labour unrest again in the port in which all the unions without any kind of distinction are unitedly protesting against the effort of this Board.

All I want to say finally is that it is very invidious also to have this kind of contrast in the welfare conditions of the dock workers and port trust workers who are working side by side on the same vessel and in the same area. It creates an irritant in the minds of dock workers for no fault of theirs. Why should they be denied of any kind of housing facilities, proper hospitalisation, proper medical facilities and so on? Why should their representatives be not included in the administrative body?

This Bill has got nothing in it. There is nothing controversial in the Bill. Of course, it will be passed. But I would request him to take this matter very seriously and see to it, particularly, that dock workers should be included in the definition of "industrial workers" so that they can benefit from the housing schemes and so on which the Government provides financial assistance for and that these glaring scandals which are going on in the Calcutta Port, particularly, are removed.

SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam): Mr. Chairman, Sir, this is the fourth amendment with regard to this Act of 1948. The first was in 1951, the second was in 1962 and the third was in 1970.

While the fourth amendment, the amending Bill, was moved, the hon. Minister cited some reasons. But having experience of some of the dock labour problems, I went through the original Bill and the parent Act, to find out what were the objects and reasons of the Bill and how far it is relevant to the present conditions of our country.

On 13th September, 1947, the Bill was presented by Shri Jagjivan Ram. In the Statement of Objects and Reasons, it was stated:

> "The demand for dock labour is intermittent depending on the arrival and departure of vessels, the size and nature of their cargo as well as seasonal and cyclical fluctuations."

Another reason is given that of "hardship due to unemployment". Further on, it is stated, what are the aims of the scheme. One is, "registration of dock workers with a view to securing greater regularity of employment and regulating the employment of dock workers, whether registered or not in a part." Further down, there is a mention of "terms and conditions of employment", etc. etc.

MR. CHAIRMAN: The hon. Member may continue his speech tomorrow. We are taking up the Discussion under Rule 193.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): Sir, if I may make a request, this Bill is a small Bill; as a matter of fact, if you allow half an hour more to discuss this Bill, this Bill will be over and then we can take up the next item.

MR. CHAIRMAN: I shall have no objection, if the House agrees. I think the House agrees to that?

SHRI INDRAJIT GUPTA: How can we guarantee that this will be over in half an hour? This may not be over in half an hour; then what will happen to the other Motion?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: That Motion will be taken up.

SHRI INDRAJIT GUPTA: Are you taking the responsibility to see that this will be over in half an hour?

SHRI BHISHMA NARAIN SINGH: I cannot do that; I can only make a request to the Chair and if the Chair wants, it will definitely be over.

MR. CHAIRMAN: This is not a controversial Bill. That is why I tried

[Mr. Chairman]

to collect the consensus of the House and it seems the House is ready to do that.

DR. KARAN SINGH: (Udhampur): The next Motion is very important. Provided this is finished in half an hour, there should be no objection; but it should not, after half an hour, drag on further.

MR. CHAIRMAN: I think half an hour will be sufficient. Two hours were allotted but, then....

SHRI INDRAJIT GUPTA: I think it is better that it continues tomorrow and we let the other Motion come.

MR. CHAIRMAN: Now that we have collected the consensus of the House, let us stick to it. The House also probably wants it. Now, Mr. Arakal. Only the salient points.

SHRI XAVIER ARAKAL: I will not take much time.

My first submission is that this amendment is a patch-work on an old cloth. The entire legal system and laws relating to the docks and dock workers have to be re-assessed and re-evaluated and a new, up-to-date enactment has to be brought in. The previous speakers have pointed out many of the defects in our system, but one thing that I would like to say with regard to this Bill is this. Why should it be confined to only seven ports? Why should it be confined to major ports alone? If you refer to the definition of dock workers in the parent Act, it is a term which can and should be interpreted in a wider sense. It says 'A dock worker means a person employed or to be employed in, or in the vicinity of....' and it goes on. I wish I had the time to read it, but I am cutting it short.

My first request is that there should not be this discrimination of taking only seven major ports while we have many other ports as well, and minor ports also, wherein there are many dock workers. We should have a comprehensive approach. I hope this suggestion will be taken into consideration by the hon. Minister.

Another point is that, as Mr. Indrajit Gupta has said, we should be told what are the activities of the Welfare Board, how much money they have collected, how much money they have spent and in what manner, who are the recipients and how far it has improved the condition of the workers. It is high time that the House is told what are the activities of this welfare scheme and its relevance to our day to day life. Of course there is a Board as well as an Advisory Committee. But, as the earlier speakers have pointed out, it is time to have another look at them—who are those people in this Board and who are managing and administering the day to day affairs of this system.

The other major problem is the poor relationship among the Port Trust, the dock workers, the public and the officers. This poor relations is creating untold miseries both for the workers as well as for the public. May I cite the incident of the Cochin Port? For a small matter, the workers were forced to go on strike, causing every day a loss of over Rs. 5 crores. Is it a small amount? What were the repercussions of that incident on the development of this country and of that area?

Now, there is a problem at the Calcutta Port. Due to non-payment of some salaries and wages, the ship is held up there. My submission is that this has been created because of the poor relations between the Port Trust and the dock workers. This is something which can be avoided.

Another point I would like to raise is that. Under whose control and supervision does the Port Trust area come? Who is the authority to police this area? Does it come under the Central Government or does it come under the supervision of the State Government? If the State

Government is not willing to extend its help, what is the method? My submission is that the port area should be brought under the control of the Central Government. There are also complaints from many ship-owners that the ships are not properly looked after while they are anchored in the ports and that the cargo is being taken away by miscreants. Why does it happen? There is lot of pilferage. We hear many complaints from the ship-owners. I would like to know what is the scheme, what is the method, by which we can prevent this. As I said earlier, this Amendment is only a patch-work on an old cloth. You have to bring forward a comprehensive enactment. Unless you bring forward a comprehensive enactment, the same state of affairs will continue. Though the parent Act was enacted in 1948, we have not gone further.

There is a peculiar system among the Dock workers with regard to their employment. May be, Mr. Indrajit Gupta knows about it. It is a closed-door system. They would not allow anybody to come and work there. If you want to get a job there you have to pay a high premium...

SHRI INDRAJIT GUPTA: He has to be a registered worker.

SHRI XAVIER ARAKAL: He has to be a registered worker; he has to come under the scheme. Suppose he is not a registered worker, he does not come within the ambit of the scheme. There is employment opportunity, but it is not easy to get employment under the present conditions in many of these ports.

Therefore, my submission is that, though we are validating something which ought to have been done earlier with regard to the financial aspect of the Dock Labour Board—, it is high time that we look into the other aspects also and try to bring forward a comprehensive enactment taking all the aspects into consideration.

With these words, I support this Amendment.

15.39 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE—*Contd.*

REPORT OF DINESH SINGH COMMITTEE ON TRIPURA AND A STATEMENT

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): I have great pleasure in laying the Report of the Dinesh Singh Committee on Tripura on the Table of this House. In view of the urgency of the matter and also of the bulk of the Report alongwith its annexure, it has not been possible to lay simultaneously the Hindi version of the Report on the Table of the House today. Such Hindi copies of the Report would be laid on the Table of the House at the earliest opportunity. [*Placed in Library. See* No. LT-1253/80].

PROF. N. G. RANGA (Guntur): What is this Report about?

SHRI YOGENDRA MAKWANA: On Tripura.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): Let us have a discussion on it also.